फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 67 प्रभात जयपुर, बुधवार 7 अक्टूबर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com



The Story Of Bengali Chhena And Sandesh

The French traveller, François Bernier, wrote: 'Bengal is celebrated for its sweetmeats, especially in places inhabited by the Portuguese, with whom they are an article of considerable trade.'

Could Camel Tears Inspire the Next Generation of Antivenoms?

कांग्रेस काफी खुश है, राहुल द्वारा धरने के कार्यक्रम में अचानक बदलाव लाने से

'धरना खत्म हो जाता, लेकिन, राहुल अचानक बस में बैठते-बैठते आकाशवाणी भवन में घुस गए तथा वहाँ धरने पर बैठ गए'

- अगर कथानक (स्क्रिप्ट) में परिवर्तन नहीं लाया गया होता तो धरना बड़े शांतिपूर्ण तरीके, बिना किसी नाटकीय ट्विस्ट के कभी का खत्म हो गया होता।
- कांग्रेस काफी चटकारे लेते हुए, सोशल मीडिया पर सुना रही है, ''आकाशवाणी से जन की बात'', प्र.मंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम ''मन की बात'' की खिल्ली उड़ाने का प्रयास करते हुए।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। संसद भवन से चुनाव आयुक्तों से मिलने के लिए इंडिया ब्लॉक के तयशुदा मार्च ने अचानक एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन तथा वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आकाशवाणी भवन में अचानक धरना शुरू कर दिया। इससे पहले दोनों नेताओं और अन्य सांसदों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर बस में बैठा दिया था।

विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया और दिल्ली के अलग-अलग पुलिस थानों में ले जाने के लिए बसों में बैठाया गया। विरोध प्रदर्शन लगभग खत्म हो चुका था, तभी भाई-बहन ने अचानक ऐसा कदम उठाया, जिससे कांग्रेस के नेता भी हैरान रह गए।

प्रियंका गांधी पहले से ही ऑल इंडिया रेडियो के मुख्यालय आकाशवाणी भवन के बाहर खड़ी एक बस में बैठी थीं और राहुल गांधी बस में चढ़ने वाले थे। अचानक दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा और फिर पुलिसकर्मियों के पास से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन के परिसर में चले गए। यह कदम पहले से तय योजना का हिस्सा नहीं था और शुरुआत में पुलिसकर्मियों को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए।

राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 4 की दीवार फांदकर परिसर में दाखिल हो गए। पवन खेड़ा सहित, कांग्रेस के अन्य सांसदों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भवन में प्रवेश करने की कोशिश की।

गांधी परिवार के दोनों नेताओं के अंदर जाने के बाद, कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल और पवन खेड़ा ने आकाशवाणी भवन की चारदीवारी पर चढ़कर नारे लगाने शुरू कर दिए। इमरान प्रतापगढ़ी और श्रीनिवास बी.वी. भी उनके साथ शामिल हो गए।

कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को लगा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो चुका है। आकाशवाणी भवन के बाहर मौजूद कांग्रेस के एक सांसद ने कहा, ''हमें नहीं पता कि क्या हुआ। यह योजना का हिस्सा नहीं था। जब वे (राहुल एवं प्रियंका) अंदर गए तो उनके मन में क्या था, यह सिर्फ वे दोनों जानते हैं।''

कांग्रेस के नेता अभी भी परिसर में डटे हुए हैं और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अब आकाशवाणी भवन के बाहर तैनात हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिसर के अंदर मौजूद फोर्स का उद्देश्य नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कांग्रेस नेताओं ने, विरोध प्रदर्शन खत्म करने की पुलिस की योजना को विफल करने का श्रेय गांधी परिवार को दिया। एक नेता ने कहा, ''अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो प्रदर्शन खत्म हो गया होता।''

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''सुबह इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग की ओर जाने की कोशिश की। पुलिस ने सांसदों को जबरन रोक दिया। इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना प्रमुख नियुक्त

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर। देश के अगले वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे। अभी वे वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने उन्हें 31 अक्टूबर की दोपहर से एयर चीफ मार्शल के रैंक में 29वें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया है।

वे एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की जगह लेंगे, जो 31 अक्टूबर

- वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे।

को रिटायर हो रहे हैं। उन्हें 3,500 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग का अनुभव है। एयर मार्शल ने 05 जून को 51वें वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पद संभाला था।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल दीक्षित को 06 दिसंबर 1986 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। ऑपरेशनल फ्लाइंग, फ़्लाइट टैस्टिंग, फ़ोर्स मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में शानदार करियर वाले एयर मार्शल दीक्षित को करियर के दौरान 2026 में परम विशिष्ट सेवा पदक, 2023 में अति विशिष्ट सेवा पदक, 2006 में वायु सेना पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

300 विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी ने धरना दिया

ज्ञानेश कुमार तो उनसे नहीं मिले, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया

- पुलिस ने राहुल को वहाँ से हटाने की कोशिश की, पर राहुल ने जवाब में कहा कि विरोध प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है।
- राहुल ने यह भी तर्क दिया कि ''वोट चोरी'' देशद्रोह के समान है, क्योंकि इसके मार्फत हमसे हमारी ''डैमोक्रैसी'' छीनी जा रही है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। राहुल गांधी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। दिनभर चले मार्च, विरोध प्रदर्शन और धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया, गिरफ्तार किया, पुलिस वैन में बैठाया और किंग्सवे कैंप भेज दिया।

राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के आंदोलन का नेतृत्व किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान, सांसदों ने बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन किया, जीत के अंदाज में एक बड़ा झंडा लहराया और मोदी-शाह सरकार को चेतावनी दी कि लोगों के वोट चुराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हेर-फेर करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया, वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। उन्हें संसद मार्ग पर स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय के पास ही स्थित आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया गया।

यह दिनभर चलने वाला धरना था, जिसमें राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे।

भारी और कई स्तरों वाली बैरिकेडिंग के बीच पूरा इलाका मीडिया, कैमरों, पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों और बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस तथा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से भरा हुआ था।

बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने राहुल गांधी को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है।

काफी देर बाद शाम को पुलिस के एक बड़े दल ने उन्हें जबरन घसीटा और उठाया। राहुल गांधी ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया।

यह दृश्य उस घटना की याद दिलाता है, जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने के बाद उन्हें (राहुल गांधी को) वहां से हटाया गया था। उस समय वे जंतर-मंतर पर सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यह उस घटना की भी याद दिलाता है, जब अमित शाह के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च कर रहे युवा छात्रों के साथ मारपीट की थी।

इस बार मार्च मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर है। उन पर मतदाता सूची में हेरफेर करने और भाजपा को चुनाव जिताने के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नवीन पटनायक की पार्टी ''इण्डिया ब्लॉक'' के नज़दीक आ रही है?

आज राहुल गांधी द्वारा मु.चुनाव आयुक्त के विरूद्ध किए गए धरने प्रदर्शन में बी.जे.डी. का शामिल होना, क्या, ऐसे परिवर्तन का संकेत है!

- हालांकि, अभी बी.जे.डी. का स्थानीय व क्षेत्रीय सत्ता के विकेन्द्रीयकरण पर दबाव रहने के कारण, बीजेडी का इण्डिया ब्लॉक में स्थायी तौर पर सदस्यता लेना कुछ नामुमकिन सा माना जा रहा है।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। आज चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में नवीन पटनायक की बीजेडी (बीजू जनता दल) की भागीदारी ने इंडिया गठबन्धन और खास तौर से कांग्रेस के अन्दर इस संभावना की उम्मीद पैदा की है कि आने वाले समय में बीजेडी, कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी बनाए रखने की अपनी नीति पर पुनर्विचार कर सकती है।

बीजेडी सांसद मानस मंगराज और सुलता देव ने आज नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च में हिस्सा लिया। ज्ञातव्य है कि यह मार्च स्पैशल इंटैंसिव रिविज़न (एस.आई.आर.) के दौरान हुई कथित अनियमितताओं तथा बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाये जाने के विरोध में आयोजित किया गया था। विपक्ष ने इन आरोपों को ''वोट चोरी'' का नाम दिया है। लेकिन बीजेडी ने तुरंत स्पष्ट किया कि यह किसी नए गठबंधन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान को तीन नई ट्रेन मिलीं

जयपुर, 6 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश में परिवहन सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन नई रेल गाड़ियों के परिचालन को मंजूरी दी है।

इस स्वीकृति के अनुसार, भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस (वाया

- मुख्यमंत्री भजनलाल के आग्रह पर रेल मंत्री ने मंजूरी दी।

कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं भरतपुर), हरिद्वार ओखा एक्सप्रेस (वाया अलवर, जयपुर, अजमेर एवं आबू रोड) और हरिद्वार वेरावल एक्सप्रेस (वाया अलवर, जयपुर, अजमेर एवं आबू रोड) का परिचालन किया जाएगा।

नई रेल गाड़ियों के परिचालन से प्रदेश में क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ होगा, जिससे कई जिलों में यात्रियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में किए गए संशोधन वापस लिए

एस.आई.आर. के तहत, व्यक्ति के माँ-बाप व दादा-दादी, नाना-नानी से जोड़ने वाली जानकारी की आवश्यकता को जरूरी नहीं माना जाएगा

- अतिरिक्त वंशावली वाली घोषणा को ई.सी.आई.एन.ई.टी. पोर्टल, ऐप तथा चुनाव अधिकारियों के पोर्टल्स से भी हटा दिया गया है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (फॉर्म 6) के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी देने से इनकार करने के एक दिन बाद, चुनाव आयोग ने मंगलवार को उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त स्पैशल इंटैंसिव रिविज़न (एसआईआर) घोषणा को वापस ले लिया, जहाँ रिविज़न की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

अतिरिक्त वंशावली घोषणा, जिसमें आवेदकों से खुद को या अपने माता-पिता/दादा-दादी को पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए कहा गया था, उसे गैर-एसआईआर और पूरी हो चुकी प्रक्रियाओं वाले क्षेत्रों के लिए ईसीआईनेट पोर्टल, ऐप और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पोर्टलों से हटा दिया गया है।

जहां यह अभी लागू है: जिन राज्यों में स्पैशल इंटैंसिव रिविज़न (एसआईआर) की प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां अतिरिक्त घोषणा की आवश्यकता बनी हुई है।

सामान्य फॉर्म फिर से लागू: जिन क्षेत्रों में पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां पहली बार आवेदन करने वाले और नए आवेदकों को अब केवल ''रजिस्ट्रेशन ऑफ इलैक्टर्स रुल्स 1960'' के तहत आने वाले नियमित, कानूनी फॉर्म 6 को भरना होगा।

आंतरिक आपत्तियां: यह फैसला चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों और आंतरिक जाँच के बाद वापस लिया गया। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या कानून के तहत नियमों में औपचारिक बदलाव किए बिना डिजिटल आवेदन प्रक्रिया में संशोधन करना उचित था।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वैधानिक फॉर्म में किसी भी तरह का बदलाव उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, न कि केवल प्रशासनिक स्तर पर एकतरफा तरीके से। कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से इस संबंध में आधिकारिक रिकॉर्ड भी मांगे।

ईसीआईनेट पर मतदाता फॉर्म 6 से बिना मंजूरी वाली एसआईआर घोषणा हटाई गई।

कार्रवाई: चुनाव आयोग ने ईसीआईनेट पोर्टल पर फॉर्म 6 से बिना मंजूरी वाली स्पैशल इंटैंशिव रिविज़न (एसआईआर) घोषणा को हटा दिया।

